

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या – 59/2025  
(अपील संख्या – 1971/2024)

द्वारका प्रसाद शर्मा

—प्रार्थी—अपीलार्थी

बनाम

1. श्री भास्कर ए सांवत, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. श्री अखिल अरोडा, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. श्री दिनेश गोयल, मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, 2 सिविल लाईन, जेकब रोड (जल भवन) जयपुर।
4. श्री मदन मोहन रावत, अधीक्षण अभियंता, (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, 2 सिविल लाईन, जेकब रोड, (जल भवन) जयपुर।
5. श्री केशव पाण्डे, अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (कृष्णा नगर) सर्किल, भरतपुर।
6. श्री महेन्द्र सिंह, सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपखंड, बयाना, जिला भरतपुर।
7. श्री चमन प्रकाश जोरवाल, लेखाधिकारी, (वर्तमान वरिष्ठ लेखाधिकारी) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (कृष्णा नगर) सर्किल, भरतपुर।

—अप्रार्थीगण—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.03.2025  
आदेश की दिनांक : 29.07.2025

उपस्थित :-

प्रार्थी—अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक  
अप्रार्थी—प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- चेतन राम देवड़ा, सदस्य  
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

## आदेश

1. प्रार्थी—अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया है कि अप्रार्थीगण—प्रत्यर्थीगण ने अधिकरण के अपील संख्या 1971/2024 में दिनांक 03.01.2025 को पारित आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की है।

## अधिकरण के पूर्वोक्त आदेश दिनांक 03.01.2025 का प्रभावी भाग (Operating Part) निम्न प्रकार है :-

‘प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चौकीदार के पद पर नियमित वेतन श्रृंखला में हुई थी और अपीलार्थी को आदेश दिनांक 28.01.1991 के द्वारा नियम, 1973 के अंतर्गत सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई और वित्त विभाग के अधिसूचना दिनांक 02.02.1997 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धियां भी दी गई। अपीलार्थी की नियुक्ति नियमित नियुक्ति दिनांक 03.08.1985 को की गई और उसे 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ तथा 27 वर्ष की सेवा होने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 17.01.2017 के द्वारा दिया गया। अपीलार्थी वर्ष 1985 से कार्य कर रहा है और उसे वर्ष 1991 में सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई तथा द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ भी दिया गया और उसे मीटर रीडर के पद पर रिक्ति वर्ष 2016-17 के पद के विरुद्ध पदोन्नत किया गया। जहां तक अपीलार्थी को वरिष्ठता सूची दिनांक 28.08.2023 में अपीलार्थी के नाम पर दिनांक 01.04.2023 से मीटर रीडर कैडर में विचार करते हुये उसे अग्रिम पदोन्नति मीटर इंसपेक्टर के पद पर पदोन्नत नहीं करते हुये तथा राजस्थान इंजीनियरिंग एलाईड पोस्ट सर्विस रूल्स, 1968 (धारा 29) के अंतर्गत अपीलार्थी को फिटर-II, फिटर-I एवं फोरमैन द्वितीय मानते हुये अपीलार्थी को समस्त पदोन्नति लाभ नहीं दिये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पदोन्नति ट्रेड विकल्प के आधार पर अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त भरतपुर के आदेश दिनांक 05.08.2018 के द्वारा सहायक से मीटर रीडर प्रथम के पद पर पदोन्नति कर वर्ष 2016-17 आवंटित की गई। परंतु यह भी सही है कि अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति अधिकरण के आदेश दिनांक 16.08.2016 की पालना में प्रदान की गई है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कार्मिक श्री मोहन सिंह जिसकी प्रथम नियुक्ति बेलदार के पद पर हुई थी और वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13.03.2023 के अनुसार बेलदार का नाम सहायक कर दिया गया और मोहन सिंह को फिटर कैडर में चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। जबकि अपीलार्थी भी सहायक के पद पर नियुक्त था और उसे मीटर रीडर के पद पर पदोन्नत करते हुये लाभ दिया गया। जबकि श्री मोहन सिंह को फिटर कैडर में चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है, जो हमारे मत में समान पद पर दोनों कार्मिक पदस्थापित होने के बावजूद अलग-अलग कैडर में नियुक्त किया जाना एवं वेतनमान में भी अंतर होना उचित प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार समान पद पर एवं समान योग्यता के आधार पर दोनों कार्मिक समान पदोन्नति एवं वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। अतः अपीलार्थी भी राजस्थान इंजीनियरिंग एलाईड पोस्ट सर्विस रूल्स, 1968 (धारा 29) के अंतर्गत फिटर-II, फिटर-I एवं फोरमैन द्वितीय के समान वेतनमान का लाभ जो कार्मिक श्री मोहन सिंह को प्रदान किये गये हैं, अपीलार्थी भी उक्त लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाये योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वरिष्ठता सूची दिनांक 28.08.2023 में मीटर रीडर कैडर में दिनांक 01.04.2023 से अपीलार्थी योग्य पाये जाने पर उसके नाम पर विचार करते हुये उसे अग्रिम पदोन्नति मीटर इंसपेक्टर के पद पर नियमानुसार पदोन्नत करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावे तथा राजस्थान इंजीनियरिंग एलाईड पोस्ट सर्विस रूल्स, 1968 (धारा 29) के अंतर्गत अपीलार्थी को फिटर-II, फिटर-I एवं फोरमैन द्वितीय मानते हुये अपीलार्थी को समस्त पदोन्नति लाभ प्रदान किये जावे तथा चयनित वेतनमान आदि का लाभ भी नियमानुसार दिये जाने के आदेश फरमाये जावें।’

- उनका आगे अभिकथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 03.01.2025 की बिना उचित कारण के जानबूझ कर अवहेलना की जा रही है, जो कि माननीय अधिकरण के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना

है। अपीलार्थी ने अधिकरण के आदेश की पालना करवाये जाने के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 09.01.2025, 22.01.2025 एवं 03.02.2025 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया गया। इसके पश्चात् अपीलार्थी ने दिनांक 24.02.2025 को अधिकरण के आदेश की अवमानना के संबंध में लीगल नोटिस भी प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किये हैं। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग जानबूझ कर अधिकरण के आदेश की पालना नहीं कर रहा है। इसलिए माननीय अधिकरण के आदेशों की अवहेलना के दोषी है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि प्रत्यर्थी विभाग से माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 03.01.2025 की पालना करवायी जावे और पालना नहीं करने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही प्रारम्भ कर माननीय उच्च न्यायालय को दण्ड हेतु रैफर किया जावे।

3. अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण की ओर से नोटिस के बावजूद इस अवमानना याचिका का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. हमने उभय पक्षकारों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी-अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अवमानना प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया।
5. स्वीकृत रूप से अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.01.2025 के क्रियाशील भाग में यह अंकित किया गया है कि :-

‘प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चौकीदार के पद पर नियमित वेतन श्रृंखला में हुई थी और अपीलार्थी को आदेश दिनांक 28.01.1991 के द्वारा नियम, 1973 के अंतर्गत सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई और वित्त विभाग के अधिसूचना दिनांक 02.02.1997 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धियां भी दी गई। अपीलार्थी की नियुक्ति नियमित नियुक्ति दिनांक 03.08.1985 को की गई और उसे 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ तथा 27 वर्ष की सेवा होने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 17.01.2017 के द्वारा दिया गया। अपीलार्थी वर्ष 1985 से कार्य कर रहा है और उसे वर्ष 1991 में सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई तथा द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ भी दिया गया और उसे मीटर रीडर के पद पर रिक्ति वर्ष 2016-17 के पद के विरुद्ध पदोन्नत किया गया। जहां तक अपीलार्थी को वरिष्ठता सूची दिनांक 28.08.2023 में अपीलार्थी के नाम पर दिनांक 01.04.2023 से मीटर रीडर कैडर में विचार करते हुये उसे अग्रिम पदोन्नति मीटर इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत नहीं करते हुये तथा राजस्थान इंजीनियरिंग एलाईड पोस्ट सर्विस रूल्स, 1968 (धारा 29) के अंतर्गत अपीलार्थी को फिटर-II, फिटर-I एवं फोरमैन द्वितीय मानते हुये अपीलार्थी को समस्त पदोन्नति लाभ नहीं दिये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पदोन्नति ट्रेड विकल्प के आधार पर अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त भरतपुर के आदेश दिनांक 05.08.2018 के द्वारा सहायक से मीटर रीडर प्रथम के पद पर पदोन्नति कर वर्ष 2016-17 आवंटित की गई। परंतु यह भी सही है कि अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति अधिकरण के आदेश दिनांक 16.08.2016 की पालना में प्रदान की गई है। परंतु प्रत्यर्थी

विभाग द्वारा कार्मिक श्री मोहन सिंह जिसकी प्रथम नियुक्ति बेलदार के पद पर हुई थी और वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13.03.2023 के अनुसार बेलदार का नाम सहायक कर दिया गया और मोहन सिंह को फिटर कैडर में चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। जबकि अपीलार्थी भी सहायक के पद पर नियुक्त था और उसे मीटर रीडर के पद पर पदोन्नत करते हुये लाभ दिया गया। जबकि श्री मोहन सिंह को फिटर कैडर में चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है, जो हमारे मत में समान पद पर दोनों कार्मिक पदस्थापित होने के बावजूद अलग-अलग कैडर में नियुक्त किया जाना एवं वेतनमान में भी अंतर होना उचित प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार समान पद पर एवं समान योग्यता के आधार पर दोनों कार्मिक समान पदोन्नति एवं वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। अतः अपीलार्थी भी राजस्थान इंजीनियरिंग एलाईड पोस्ट सर्विस रूल्स, 1968 (धारा 29) के अंतर्गत फिटर-II, फिटर-I एवं फोरमैन द्वितीय के समान वेतनमान का लाभ जो कार्मिक श्री मोहन सिंह को प्रदान किये गये हैं, अपीलार्थी भी उक्त लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाये योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वरिष्ठता सूची दिनांक 28.08.2023 में मीटर रीडर कैडर में दिनांक 01.04.2023 से अपीलार्थी योग्य पाये जाने पर उसके नाम पर विचार करते हुये उसे अग्रिम पदोन्नति मीटर इंसपेक्टर के पद पर नियमानुसार पदोन्नत करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावे तथा राजस्थान इंजीनियरिंग एलाईड पोस्ट सर्विस रूल्स, 1968 (धारा 29) के अंतर्गत अपीलार्थी को फिटर-II, फिटर-I एवं फोरमैन द्वितीय मानते हुये अपीलार्थी को समस्त पदोन्नति लाभ प्रदान किये जावे तथा चयनित वेतनमान आदि का लाभ भी नियमानुसार दिये जाने के आदेश फरमाये जावें।"

6. यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अधिकरण ने प्रार्थी-अपीलार्थी की पूर्वोक्त अपील में आदेश पारित कर अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण को कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। इस प्रकार यह स्वतः स्पष्ट है कि अधिकरण के द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण ने अभी तक नहीं की है। अतः अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण के लिये यह आवश्यक था कि वे अधिकरण के आदेश की समयावधि में पालना करते या माननीय उच्च न्यायालय से इसकी क्रियान्विति पर कोई स्थगन आदेश प्राप्त करते। प्रिवी काउन्सिल के सर लॉरेन्स जेनकिन्स ने जसकर्ण बोइद बनाम पिस्थीचन्द लाल (ए.आई.आर. 1918 पी.सी. 151) के प्रकरण में निम्न प्रकार अवधारित किया था :-

*"whatever be the theory under other systems of law, under the Indian law and procedure an original decree is not suspended by the presentation of an appeal nor is its operation interrupted where the decree on appeal is merely one of dismissal. There is nothing in the Indian law to warrant the suggestion that the decree or order of the court or tribunal of the first instance becomes final only on the termination of all proceedings by way of appeal or revision."*

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह (ए.आई. आर. 1958 एस.सी. 86) में प्रिवी कौंसिल के पूर्वोक्त निर्णय का अनुमोदन करते हुए निम्न मत व्यक्त किया था :-

*"the filing of an appeal might put the decree or order in jeopardy but until it is reversed or modified it remains effective."*

8. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पी.डी.देसाई ने हंसराज धीर के प्रकरण (1985 Cri. L.J. 1030) में अवमानना प्रकरण के सिद्धान्तों की निम्न प्रकार व्याख्या की थी :-

*"Once a case is decided, it is the bounden duty of the State and its subordinates to implement, with the utmost expedition, the said decision. In a Government which is ruled by law, there must be complete awareness to carry out faithfully and honestly the decisions rendered by courts of law after effective adjudication. Then only will private individuals, organisations and institutions learn to respect the decisions of courts. In absence of such attitude on the part of all concerned, chaotic conditions might arise and the functions assigned to the courts of law under the Constitution might be rendered a futile exercise. It requires to be emphasised, in this connection, that mere preferment of an appeal does not automatically operate as a stay of the decision under appeal and that till an application for stay is moved and granted by the appellate court, or, in the alternative, the court which rendered the decision is moved and grants an interim stay of the decision pending the preferment of an appeal and grant of stay by the appellate court, the decision continues to be operative. Indeed, non-compliance with the decision on the mere ground that an appeal is contemplated to be preferred or is actually preferred, and that, therefore, the matter is subjudice, may amount to contempt of court punishable under the Contempt of Courts Act, 1971."*

9. उपर्युक्त विनिश्चयों के आलोक में और प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विनम्र मतानुसार यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण ने इस अधिकरण के आदेश दिनांक 03.01.2025 की पालना न कर उक्त न्यायिक आदेश की अवमानना कारित की है। हम इस अवमानना प्रकरण को अधिकरण में लम्बित रखना उचित नहीं समझते हैं और इस प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 10 के प्रावधान के क्रम में उपर्युक्त अवमानना कृत्य के लिए

अवमाननाकर्ताओं के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु संदर्भित करना उचित समझते हैं।

10. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी-अपीलार्थी के अवमानना प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अधिकरण के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के अन्तर्गत अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ, जयपुर को संदर्भित करावें।

(लेखराज तोसावड़ा)  
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)  
सदस्य